

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

श्री सब्बरवाल पुत्र आनन्द प्रकाश,
डायरेक्टर स्ट्रलिंग कान्स्ट्रक्टर एवं बिल्डर्स प्रा.लि.,
ई-3/46, अरेरा कालोनी, भोपाल.

— आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल व अन्य

— अनावेदक

: आदेश :

(दिनांक 17 जनवरी, 2006 को पारित)

विषय : स्ट्रलिंग ग्रीन व्हीव - 2, चूना भट्टी, भोपाल प्रोजेक्ट के बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु जमा किए गए सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जस रु. 409400/- एवं सुपरविजन चार्जस रु. 92343/- कुल रु. 501743/- को वापिस करने हेतु म.प्र. विद्युत मण्डल को निर्देशित करने हेतु याचिका ।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री विनय शर्मा, अभिभाषक उपस्थित ।

अनावेदक श्री एम.एस. आप्टे - ए.एस.ई. (दक्षिण) उपस्थित ।

याचिकाकर्ता समीर सब्बरवाल बिल्डर, अरेरा कालोनी, भोपाल द्वारा यह याचिका सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जस 501743/- रु. विपक्षी विद्युत वितरण कम्पनी से वापस दिलाने हेतु मण्डल को निर्देशित करने के संबंध में दिनांक 12.10.2005 को प्रस्तुत की गई है ।

2. याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के संबंध में बतलाया गया कि प्रोजेक्ट स्ट्रलिंग ग्रीन व्हीव के 40 निवासियों को घरेलू कनेक्शन देने के विद्युतीकरण हेतु विपक्षी के समक्ष दिनांक 2.3.2004 को आवेदन प्रस्तुत किया था जिसके 39 प्लेटो हेतु 178 के.डब्ल्यू विद्युत भार की आवश्यकता बताई गई थी । तदनुसार विपक्षी द्वारा आवेदक की मांग ... पत्र दिनांक 31.3.2004 द्वारा स्वीकृत करते हुए रुपये 92343 के सुपरवीजन चार्जस सहित रुपये 501743 का डिमांड नोट आवेदक को दिया गया । आवेदक द्वारा उक्त राशि दिनांक 13.4.2004 को विपक्षी को दे दी गई । आवेदक द्वारा राशि वित्तीय वर्ष 2003-04 के बजाय 2004-05 में जमा की गई, इस कारण सुपरवीजन चार्जस की FY 05 के अनुसार गणना की जाकर आवेदक को 4508 रुपये की अतिरिक्त राशि को शामिल करते हुए संशोधित मांग पत्र रूपयें 506251 का प्रार्थी को दिनांक 24.01.05 को दिया गया । उक्त राशि आवेदक ने 25.1.2005 को जमा करा दी ।

3. याचिकाकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि सप्लाइ कोड की कण्डिका 4.32 में संशोधन के अनुसार सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग चार्जस, केपेसिटी बिल्डिंग चार्जस एवं पावर सब स्टेशन के अतिरिक्त का व्यय लाईसेंसी द्वारा यानि विपक्षी द्वारा वहन किया जाना है । इसके कारण याचिकाकर्ता द्वारा

उक्त कार्य हेतु जमा कराई गई कुल राशि 506251/- विपक्षी से वापस दिलाने हेतु विपक्षी को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया ।

4. उपर्युक्त याचिका के संबंध में विपक्षी द्वारा आयोग को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व दिनांक 15.9.05 को एक आवेदन प्रस्तुत कर यह राशि वापसी का अनुरोध किया था जिस पर मण्डल के पत्र क्र. 5443 दिनांक 21.9.05 द्वारा उसे वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । वास्तविकता यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाने के लिये गलत अर्थ लगाया जा रहा है । याचिकाकर्ता का परिसर कालोनी की श्रेणी में आता है तथा उसने 40 कनेक्शन के लिये 178 कि.वा. भार चाहा है । ऐसी स्थिति में विद्युत प्रदाय संहिता की कण्डिका 43 अनुसार "नवीन उपभोक्ताओं की मांग पूर्ति के लिये वितरण मेन के विस्तार तथा प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत का उपभोक्त अथवा उपभोक्ताओं के समूह द्वारा भुगतान आयोग के निर्धारण के अनुसार किया जावेगा" । अनावेदक के अनुसार आवेदक ने सिस्टम स्ट्रेग्थनिंग चार्जस की राशि 13.4.04 को ही जमा कर दी थी व तकनीकी स्वीकृति भी 31.3.2004 को दे दी गई थी । इस कारण याचिकाकर्ता सुपरवीजन चार्जस व सिस्टम स्ट्रेग्थनिंग चार्जस वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । याचिकाकर्ता ने यह याचिका माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर आयोग का समय व लोकधन नष्ट किया है । अतः अनावेदक द्वारा आयोग के समक्ष इस याचिका को संव्यय निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया ।

5. आज दोनो पक्षों को श्रवण किया गया । प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने व आवेदक को श्रवण करने के उपरांत, आयोग का यह मत है कि आवेदक द्वारा सिस्टम स्ट्रेग्थनिंग चार्जस 13.4.04 को ही जमा कराया था, इस कारण आवेदक को इस राशि को विपक्षी से रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । वर्ष 2005 से सुपरवीजन चार्जस की संशोधित राशि का वेलेंस रु. 4508 ही जमा किया था । आयोग के मतानुसार आवेदक को इस बारे में कथन स्पष्ट भी नहीं है । याचिका उक्त कारणों से तथ्यहीन है । इस कारण यह याचिका निरस्त की जाती है ।

उपरोक्तानुसार आदेश पारित ।

(आर. नटराजन)
सदस्य (इकोनामिक)

(डी. रायबर्धन)
सदस्य (अभि.)

(पी.के. मेहरोत्रा)
अध्यक्ष.